समक्ष: एम. एल. वर्मा जे.

श्रीमती सरूपी और अन्य, *याचिकाकर्ता,*

बनाम

हर गियान और अन्य, - उत्तरदाता।

1974 का ई.एफ.ए. नंबर 219

20 अगस्त, 1974।

***विशिष्ट राहत अधिनियम (*1963 का *XLVII) - धारा* 28 (1) - *न्यायालय द्वारा विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पारित करना? बिक्री के अनुबंध*T की - *क्या r को बिक्री विचार जमा करने के लिए एक अवधि निर्धारित करनी होगी - डिक्री में जमा करने के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है - ऐसी अवधि - क्या वह डिक्री के बाद तय और विस्तारित कर सकता है - अवधि के निर्धारण और विस्तार से पहले दूसरे पक्ष को नोटिस - यदि आवश्यक हो -* विशिष्ट के लिए डिक्री *बिना किसी डिफॉल्ट क्लॉज के बिक्री विचार जमा करने के लिए निष्पादन निर्धारण अवधि - निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं की गई - डिक्री-धारक - क्या न्यायालय द्वारा विस्तारित अवधि के भीतर डिक्री निष्पादित कर सकता है - डिक्री जिसमें निश्चित अवधि के भीतर जमा की विफलता पर वाद को खारिज करने का डिफ़ॉल्ट खंड शामिल है - न्यायालय* - क्या ऐसी अवधि बढ़ा सकता है - गलत अदालत में किए गए धन को जमा करना और न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार करना - ऐसी जमा *राशि - क्या अमान्य है।*

ये अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री तैयार करने के लिए कोई विशेष रूप निर्धारित नहीं करती है जैसा कि यह कुछ अन्य डिक्री के मामले में करता है। यह सब विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री में ठीक से शामिल हो सकता है कि वादी उस अनुबंध के प्रवर्तन का हकदार था जो प्रतिवादी ने एक निश्चित निर्दिष्ट राशि के लिए एक निश्चित संपत्ति की बिक्री के लिए उसके साथ किया था। बिक्री विचार जमा करने के लिए एक अवधि निर्धारित करने की न्यायालय की शक्ति विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रदान नहीं की गई है। आमतौर पर जब अदालतें विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पारित करती

हैं, तो वे एक समय तय करते हैं जिसके दौरान वादी को विचार का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है और इस तरह उसके पक्ष में संपत्ति के संबंध में उचित बिक्री प्राप्त होती है। लेकिन यह कानून के किसी भी प्रावधान के अनुपालन के बजाय सुविधा के उद्देश्यों के लिए अधिक किया जाता है। बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री चरित्र का अंतिम डिक्री नहीं है जो अदालत को खरीद धन जमा करने के लिए समय तय करने या बढ़ाने से पूरी तरह से रोकता है। जब कोई न्यायालय डिक्री पारित करते समय बिक्री विचार जमा करने के लिए कोई अवधि या तारीख तय नहीं करता है, तो उसके पास निस्संदेह जमा करने के लिए समय की अनुमति देने का अधिकार क्षेत्र है और विशिष्ट की धारा 28 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत इसे विस्तारित करने की अनुमति देने का भी अधिकार है।

राहत अधिनियम, 1963 (पैरा 4)

ये अभिनिर्धारित किया गया कि खरीद राशि जमा करने के लिए समय देने का मामला पूरी तरह से विवेकाधीन है। खरीद धन के भुगतान के लिए समय का निर्धारण विशिष्ट प्रदर्शन के लिए पार्टियों के बीच विवाद का हिस्सा नहीं है और समय का निर्धारण पार्टियों के किसी भी अधिकार को निर्धारित नहीं करता है। इस प्रकार, यह एक डिक्री की प्रकृति में भाग नहीं लेता है। इसलिए यह परिस्थिति कि न्यायालय उक्त समय को जमा करने या बढ़ाने के लिए समय देता है, पार्टियों के बीच किसी भी अधिकार की डिक्री या निर्णय के संशोधन का गठन नहीं करता है। समय देने या बढ़ाने वाले ऐसे आदेशों को पारित होने से पहले दूसरे पक्ष को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है।

(पैरा 4)

ये अभिनिर्धारित किया गया कि जब विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री यह नहीं बताती है कि यदि सफल वादी द्वारा निर्धारित समय के भीतर खरीद धन का भुगतान नहीं किया जाता है, तो डिक्री निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने के लिए अपनी चूक पर स्वचालित रूप से समाप्त नहीं होगी। डिक्री द्वारा अनुमत समय के भीतर जमा करने में उसकी ओर से चूक प्रतिवादी को अनुबंध की मंदी के लिए अदालत में आवेदन करने का अधिकार देगी। लेकिन जब तक वह उक्त राहत के लिए आवेदन नहीं करता है, तब तक विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री कायम रहती है और डिक्री धारक अभी भी अदालत द्वारा अनुमत या विस्तारित समय के भीतर खरीद धन जमा करके सीमा की अवधि के भीतर इसे निष्पादित कर सकता है,

ये अभिनिर्धारित किया गया कि जब न्यायालय विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री में एक निर्देश दर्ज करता है कि निर्धारित समय के भीतर खरीद धन जमा करने में चूक की स्थिति में, मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा, तो यह माना जाएगा कि न्यायालय ने भी मूल रूप से, अनुबंध के पुनर्गठन का आदेश पारित किया है, जैसा कि न्यायालय द्वारा विचार किया गया है।

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) का अंतिम भाग। यह इस तरह के डिक्री के मामले में है कि न्यायालय, जब निर्धारित समय के भीतर सफल वादी द्वारा खरीद धन जमा नहीं किया गया है, तो इसकी जमा के लिए समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। (पैरा 5 और 6)

ये अभिनिर्धारित किया गया कि *इसमें कोई* संदेह नहीं है कि यह सच है कि एक वादी को सतर्क रहना चाहिए और उचित न्यायालय में एक डिक्री के तहत राशि जमा करने का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जहां एक वादी अदालत में जाता है और उसकी सहायता मांगता है ताकि डिक्री के तहत उसके दायित्व को सख्ती से पूरा किया जा सके, यह अदालत पर निर्भर है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे सही जानकारी दी गई है। यदि किसी वादी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने में न्यायालय कोई गलती करता है, तो वादी की जिम्मेदारी, हालांकि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, कम से कम न्यायालय द्वारा साझा की जाती है। न्यायालय के किसी भी कार्य से वादी को नुकसान नहीं होना चाहिए और यह देखना न्यायालयों का परम कर्तव्य है कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय की गलती से नुकसान होता है, तो उसे उस पद पर बहाल किया जाना चाहिए जिस पर वह आसीन होता, लेकिन उस गलती के लिए। इसलिए जब किसी डिक्री के तहत धन की जमा राशि गलत अदालत में की जाती है और चूंकि ऐसी अदालत जमाकर्ता द्वारा की गई गलती में काफी योगदान देती है, तो उक्त न्यायालय में की गई जमा राशि अमान्य नहीं होती है।

निष्पादन प्रथम अपील मिस किरण आनंद, उप-न्यायाधीश* द्वितीय *श्रेणी, गुड़गांव के दिनांक 5 मार्च, 1974 के आदेश से निष्पादन कार्यवाही में निर्णय-देनदार श्रीमती सरूपी द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया।

अपीलकर्ताओं की ओर से वकील जी आर मजीठिया।

उत्तरदाताओं के लिए *एडवोकेट एम. पुंछी और सुरेश अंबा एडवोकेट्स।*

निर्णय

वर्मा, न्यायमूर्ति—निष्पादन मामले में इस अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

2. हर ज्ञान और राम्स हांसे (इसके बाद इसे कहा जाता है) ने अदालत से बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री प्राप्त की, जिसकी अध्यक्षता श्री देव राज खन्ना, अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, गुड़गांव ने श्रीमती सरूपी, उनके पति-भीम सिंह (अब मृत, माम चंद और माम चंडी क्रमशः उनके बेटे और बेटी हैं) के खिलाफ गांव-मेवला महाराजपुर की सीमा के भीतर स्थित भूमि का सम्मान करते हुए किया। इसके बाद अपीलकर्ताओं को, जो विक्रेता थे, 15 मार्च, 1961 को बुलाया गया। राम देवी, जो श्रीमती सरूपी की मां हैं, को उपरोक्त भूमि में से कुछ के पट्टेदार होने के कारण प्रोफार्मा प्रतिवादी बनाया गया था। उक्त डिक्री द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि प्रतिवादी एक महीने के भीतर अपीलकर्ताओं को 32,500 रुपये (इसके बाद राशि कहा जाता है) का भुगतान करेंगे। इसलिए

उन्होंने (प्रतिवादियों ने) 11 अप्रैल, 1961 को ट्रायल कोर्ट में अपीलकर्ताओं को भुगतान के लिए राशि जमा की। अपीलकर्ताओं और श्रीमती राम देवी ने भी इस न्यायालय में अपील करने को प्राथमिकता दी। 19 जुलाई को। 1961 में, इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि अपीलकर्ताओं को भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा और प्रतिवादी उनके द्वारा जमा की गई राशि को वापस ले सकते हैं, और उन्हें अपील में अंतिम निर्णय के अनुसार इसे फिर से जमा करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, उन्होंने ट्रायल कोर्ट से राशि वापस ले ली। अपील लंबित रहने तक भीम सिंह की मृत्यु हो गई और उनके बेटे, माम चंद और बेटी, श्रीमती माम चंडी को उनके कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में शामिल किया गया था। उक्त अपील 14 जुलाई, 1972 को खारिज कर दी गई थी। हालांकि, राशि को फिर से जमा करने के लिए कोई समय या तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था, हालांकि, निर्णय और डिक्री में दर्ज किया गया था। इस अदालत ने 14 जुलाई, 1972 को फैसला सुनाया। इसलिए, प्रतिवादियों ने राशि को फिर से जमा करने के लिए समय निर्धारित करने के लिए एक आवेदन किया और इस न्यायालय ने 7 अगस्त, 1972 के अपने आदेश द्वारा राशि को फिर से जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया। प्रतिवादियों ने राशि को फिर से जमा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए फिर से आवेदन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 7 अगस्त, 1972 के आदेश की प्रमाणित प्रति उन्हें इसके लिए आवेदन करने के बावजूद प्रदान नहीं की गई थी और ट्रायल कोर्ट ने उक्त आदेश की प्रति के बिना राशि के पुन: जमा को स्वीकार नहीं किया था। उस आवेदन पर, इस न्यायालय ने 24 अक्टूबर, 1972 के अपने आदेश द्वारा राशि जमा करने के लिए समय एक महीने के लिए बढ़ा दिया। 7 अगस्त, 1972 और 24 अक्टूबर, 1972 के ये दोनों आदेश अपीलकर्ताओं को बिना किसी नोटिस के पारित किए गए थे। प्रतिवादियों ने 24 नवंबर, 1972 को 24 अक्टूबर, 1972 के आदेश द्वारा अनुमत समय के भीतर गुड़गांव के अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी श्री तरलोचन सिंह की अध्यक्षता वाली अदालत में राशि जमा की। हालाँकि, वह श्री देव राज खन्ना के उत्तराधिकारी नहीं थे, जिन्होंने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पारित की थी, और मिस किरण आनंद उनके ;(श्री देव राज खन्ना के उत्तराधिकारी थे। इन दोनों न्यायालयों की अध्यक्षता श्री तरलोचन ने की। सिंह और मिस किरण आनंद, गुड़गांव में एक ही परिसर में स्थित हैं। जब प्रतिवादियों ने डिक्री का निष्पादन किया, तो अपीलकर्ताओं ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत आपत्तियां उठाईं, कि यह (डिक्री) निष्पादन योग्य नहीं था क्योंकि न तो डिक्री द्वारा अनुमत समय के भीतर राशि जमा की गई थी, न ही इसे उचित अदालत में जमा किया गया था। प्रतिवादियों द्वारा उक्त आपत्तियों का विरोध किया गया और निष्पादन न्यायालय ने इस मुद्दे को तैयार किया:-

"क्या डिक्री-धारक ने अदालत के आदेशों के अनुसार और उचित अदालत में अपेक्षित राशि जमा की थी? यदि नहीं, तो इसका क्या प्रभाव है?

प्रतिवादियों के पक्ष में उस मुद्दे को पाते हुए, निष्पादन न्यायालय ने उपरोक्त आपत्तियों को खारिज कर दिया। उक्त परिणाम से असंतुष्ट, अपीलकर्ता इस न्यायालय में अपील में आए हैं।

मैं

3. मोटे तौर पर ऊपर वर्णित तथ्यों को पार्टियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री जी आर मजीठिया द्वारा उठाई गई दलीलें दोहरी हैं और इन्हें निम्नानुसार तैयार किया जा सकता है:

    a. 14 जुलाई, 1972 को इस न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने का प्रभाव यह था कि ट्रायल कोर्ट की डिक्री को बहाल कर दिया गया था और इसलिए प्रतिवादियों को एक महीने के भीतर राशि को फिर से जमा करने की आवश्यकता थी, जैसा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई थी। इसका मतलब है कि वे 14 अगस्त, 1972 को या उससे पहले राशि जमा करने के लिए बाध्य थे। यह आग्रह किया गया था कि चूंकि इस न्यायालय के 7 अगस्त, 1972 और 24 अक्टूबर, 1972 के आदेश अपीलकर्ताओं के पीछे पारित किए गए थे और उन्हें नोटिस के बिना, वे अप्रभावी थे। इसलिए, श्री मजीठिया ने कहा कि चूंकि डिक्री द्वारा अनुमत अवधि के भीतर राशि का पुन जमा नहीं किया गया था, इसलिए यह (डिक्री) समाप्त हो गई थी और इसे निष्पादित नहीं किया जा सकता था।

    b. यह कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में राशि को फिर से जमा नहीं किया गया है, इसे (राशि का पुन: जमा) वैध जमा के रूप में नहीं माना जा सकता है।

4. जैसा कि सोमेश्वर दयाल और अन्य *बनाम लालमन शाह की विधवा*(ए.आई.आर. (1958) इलाहाबाद 488)

में देखा गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री तैयार करने के लिए कोई विशेष रूप निर्धारित नहीं करती है जैसा कि यह कुछ अन्य डिक्री के मामले में करता है, और न ही संहिता ऐसी डिक्री की सामग्री को इंगित करती है जैसा कि यह ओइडर एक्सएक्स द्वारा प्रदान किए गए पूर्व-अनुभव वाद में डिक्री के मामले में करता है। संहिता का नियम 14 विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री में ठीक से शामिल हो सकता है कि वादी उस अनुबंध के प्रवर्तन का हकदार था जो प्रतिवादी ने एक निश्चित निर्दिष्ट राशि के लिए एक निश्चित संपत्ति की बिक्री के लिए उसके साथ किया था। बिक्री विचार जमा करने के लिए एक अवधि तय करने की अदालत की शक्ति विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रदान नहीं की गई थी। की उपधारा (1)

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 28, जिसके संगत प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

> "जहां किसी भी मुकदमे में बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री है ..... अचल संपत्ति का भुगतान किया गया है और खरीदार... डिक्री द्वारा अनुमत अवधि के भीतर या ऐसी आगे की अवधि के भीतर, जिसे अदालत अनुमति दे सकती है, खरीद-धन या अन्य राशि का भुगतान नहीं करता है जिसे अदालत ने उसे भुगतान करने का आदेश दिया है। यह उसी मुकदमे में लागू हो सकता है जिसमें डिक्री की गई है, अनुबंध को रद्द किया जा सकता है और इस तरह के आवेदन पर अदालत, आदेश द्वारा, अनुबंध को रद्द कर सकती है, जहां तक डिफ़ॉल्ट रूप से या पूरी तरह से, जैसा कि मामले के न्याय की आवश्यकता हो सकती है।

बल्कि एक विपरीत इरादे को इंगित करता है। उक्त प्रावधान इंगित करता है कि डिक्री के एक पक्ष के डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में, दूसरा पक्ष अदालत का रुख कर सकता है जिसने अनुबंध की पुनरावृत्ति के लिए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री प्रदान की। सच है, आमतौर पर जब अदालतें विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पारित करती हैं, तो वे एक समय तय करते हैं जिसके दौरान वादी को विचार का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है और इस तरह उसके पक्ष में संपत्ति के संबंध में उचित बिक्री प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानून के किसी भी प्रावधान के अनुपालन के बजाय सुविधा के उद्देश्यों के लिए अधिक किया गया है। बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री चरित्र का

अंतिम डिक्री नहीं है जो अदालत को खरीद धन जमा करने के लिए समय तय करने या बढ़ाने से पूरी तरह से रोकता है। यह नियम कि अपीलीय न्यायालय के पास मूल न्यायालय के समान शक्तियां हैं और वह वही कर सकती है जो मूल न्यायालय ने किया था, अकाट्य है। जब इस न्यायालय ने 14 जुलाई, 1972 को अपील को खारिज करते हुए राशि को फिर से जमा करने के लिए कोई अवधि या तारीख तय नहीं की, तो निस्संदेह इसे फिर से जमा करने के लिए 7 अगस्त, 1972 को एक महीने का समय देने और 24 अक्टूबर, 1972 को समय के विस्तार की अनुमति देने का अधिकार था, जिसमें जमा की अवधि को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। 1972, विशिष्ट रेलीफ अधिनियम की धारा 28 (आई) के प्रावधानों के तहत। खरीद राशि जमा करने के लिए समय देने का मामला विशुद्ध रूप से विवेकाधीन है। खरीद धन के भुगतान के लिए समय का निर्धारण विशिष्ट प्रदर्शन के लिए पार्टियों के बीच विवाद का हिस्सा नहीं है और यह (समय का निर्धारण) पार्टियों के किसी भी अधिकार को निर्धारित नहीं करता है। इस प्रकार, यह एक डिक्री की प्रकृति में भाग नहीं लेता है। इसलिए, इस न्यायालय ने 7 अगस्त, 1972 को जिस परिस्थिति की अनुमति दी, वह राशि फिर से जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था या यदि 24 अक्टूबर, 1972 को बढ़ाया जाता है, तो उक्त समय एक और महीने तक, पार्टियों के बीच किसी भी अधिकार के डिक्री या निर्णय के संशोधन का गठन नहीं करता है। इसलिए, इन दोनों आदेशों को पारित करने से पहले अपीलकर्ताओं को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, इसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अपीलकर्ताओं के पीछे इसे पारित किया गया था। यहां तक कि तर्क के लिए यह मानते हुए भी कि उक्त आदेश, समय और समय के विस्तार की अनुमति देते हैं, इस आधार पर खारिज किए जा सकते हैं कि इसे पारित करने से पहले अपीलकर्ताओं को कोई नोटिस नहीं भेजा गया था, उक्त आदेश अभी भी वैध हैं और उन्हें अधिकार क्षेत्र के बिना पारित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, वे समीक्षा या इसी तरह के इस न्यायालय में पूछताछ किए बिना निष्पादन कार्यवाही में किसी भी हमले से मुक्त हैं।

5. जब विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री यह नहीं बताती है कि यदि निर्धारित समय के भीतर सफल वादी द्वारा खरीद धन का भुगतान नहीं किया जाता है, तो डिक्री निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने के लिए उसके (वादी के) डिफ़ॉल्ट पर स्वचालित रूप से समाप्त नहीं होगी। डिक्री द्वारा अनुमत समय के भीतर जमा करने में उसकी ओर से चूक विक्रेता को अनुबंध की वापसी के लिए अदालत में आवेदन करने का अधिकार देगी। लेकिन चूंकि वह (विक्रेता) उक्त राहत के लिए आवेदन नहीं करता है, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री कायम रहती है और डिक्री-धारक अभी भी इसे सीमा की अवधि के भीतर निष्पादित कर सकता है और अदालत द्वारा अनुमत या विस्तारित समय के भीतर खरीद धन जमा कर सकता है। इसी तरह का दृष्टिकोण *राजन पात्रो* बनाम *अकुर साहू और अन्य* (2) *में भी लिया गया था।*

6. मामला अलग हो सकता है जब न्यायालय विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री में एक निर्देश दर्ज करता है कि निर्धारित समय के भीतर खरीद धन जमा करने में चूक की स्थिति में, मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में, यह माना जाएगा कि न्यायालय ने विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के समापन भाग द्वारा विचार किए गए अनुबंध के पुनर्गठन का आदेश भी पारित किया है। यह ऐसी डिक्री के मामले में है कि न्यायालय, जब निर्धारित समय के भीतर सफल वादी द्वारा खरीद धन जमा नहीं किया गया है, तो इसकी जमा के लिए समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हो सकता है। *भूटानाथ दास और अन्य* बनाम *सहदेब चंद्र पांजा* (3) *के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय* पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने भरोसा करते हुए दलील दी कि डिक्री में

2. ए.आई.आर. 1959 उड़ीसा 74.
3. ए.आई.आर. 1962 कलकत्ता 485.

14 जुलाई, 1972 को अपील खारिज होने के बाद से एक महीने के भीतर राशि जमा करने में प्रतिवादी विफल रहे थे, यह डिक्री से संबंधित है, जो डिक्री-धारक द्वारा निर्धारित समय के भीतर जमा करने में चूक के मामले में दंडात्मक परिणाम को निर्दिष्ट करता है। इस मामले में, न तो ट्रायल कोर्ट की डिक्री और न ही 14 जुलाई, 1972 के इस न्यायालय के डिक्री में कोई निर्देश था कि यदि प्रतिवादी नियत तारीख से पहले या निर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि जमा करने में विफल रहते हैं तो मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए, *भूटानाथ दास* के मामले (सुप्रा) के तथ्य काफी अलग थे और उस मामले का निर्णय अपीलकर्ताओं को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, और यह आरोप नहीं लगाया गया है कि अपीलकर्ताओं ने समय के भीतर राशि जमा करने में प्रतिवादियों की कथित चूक के कारण अनुबंध को रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट में कोई आवेदन किया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 7 अगस्त, 1972 या 24 अक्टूबर, 1972 के इस न्यायालय के आदेश, जमा करने के लिए समय की अनुमति देना और फिर इसे विस्तारित करना, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 28 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं और वे वैध हैं। इसलिए, मुझे अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील की पहली दलील में कोई बल नहीं मिला, इसलिए मैं इसे खारिज करता हूं।

7. नाजर सिंह *बनाम मुंशी सिंह* (1970 में एल. जे. 108 ई) *इस* मामले में इस न्यायालय का ने श्री मजीठिया के दूसरे तर्क का पूरा उत्तर प्रस्तुत किया। यह एक ऐसा मामला था जहां एक प्री-खाली कर्ता ट्रायल कोर्ट में अपीलीय अदालत द्वारा अनुमत आगे की अग्रिम राशि का भुगतान करने में विफल रहा। दूसरी ओर, उन्होंने अपीलीय न्यायालय में इसे जमा कर दिया था। यह देखा गया कि निचली अपीलीय अदालत का कार्य जमा राशि को स्वीकार करने से इनकार नहीं करना और इसका भी; यह निर्देश देने में विफलता कि ट्रायल कोर्ट में जमा किया जा सकता है, अपीलीय न्यायालय में राशि जमा करने में सफल प्री-कैम्प्टर द्वारा की गई गलती में काफी योगदान दिया था।

आगे यह देखा गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक वादी को सतर्क रहना चाहिए और देखभाल करनी चाहिए, लेकिन जहां एक वादी अदालत में जाता है और अदालत की सहायता मांगता है ताकि एक डिक्री के तहत उसके दायित्व को उसके द्वारा सख्ती से पूरा किया जा सके, तो यह अदालत पर निर्भर है, अगर वह वादी को उसके स्वयं के उपकरणों पर नहीं छोड़ता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे सही जानकारी दी गई है। यदि किसी वादी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने में न्यायालय कोई गलती करता है, तो वादी की जिम्मेदारी, हालांकि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, कम से कम न्यायालय द्वारा साझा की जाती है। यदि वादी उस जानकारी के विश्वास पर कार्य करता है, तो न्यायालय उसे रोक नहीं सकता है। एक गलती के लिए जिम्मेदार जो उसने खुद की थी। उक्त मामले में आगे यह देखा गया है कि "न्यायालय के मार्गदर्शन के लिए इस सिद्धांत से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है कि अदालत के किसी भी कार्य से वादी को नुकसान नहीं होना चाहिए और यह देखना न्यायालयों का परम कर्तव्य है कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय की गलती से नुकसान होता है, तो उसे उस स्थिति में बहाल किया जाना चाहिए जिस पर वह कब्जा कर चुका था, लेकिन उस गलती के लिए। इस मामले में अपील 11 साल तक इस अदालत में लंबित रही। उक्त अवधि के दौरान, श्री देव राज खन्ना, जिन्होंने उक्त डिक्री पारित की थी, को कई अधीनस्थ न्यायाधीशों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसलिए, उत्तरदाताओं से यह जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि श्री देव राज खन्ना का उत्तराधिकारी कौन था, जब वे या उनमें से कोई भी राशि फिर से जमा करने के लिए गुड़गांव गया था। श्री तरलोचन सिंह और सुश्री किरण आनंद की अध्यक्षता वाली अदालतें गुड़गांव में एक ही परिसर में स्थित हैं। इसलिए, इन परिस्थितियों में, उत्तरदाताओं को यह मानने में गलती हो सकती थी कि श्री तरलोचन सिंह श्री देव राज खन्ना के उत्तराधिकारी थे। उक्त गलती वास्तविक हो सकती है। यदि श्री तरलोचन सिंह की अदालत ने इसके रिकॉर्ड देखे होते और प्रतिवादियों को यह जानकारी दी होती कि डिक्री उस न्यायालय से संबंधित नहीं है और इस प्रकार, उस न्यायालय में राशि जमा नहीं की जा सकती है, तो प्रतिवादियों को सही रास्ते पर लाया जा सकता था और उन्होंने श्री देव राज खन्ना के उत्तराधिकारी के न्यायालय में राशि जमा करने के लिए कदम उठाए होते। इसलिए, श्री तरलोचन सिंह की अध्यक्षता वाले न्यायालय ने उचित न्यायालय में राशि जमा करने में विफल रहने में प्रतिवादियों द्वारा की गई गलती में काफी योगदान दिया था। इसलिए, *नाजर* सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्णय को ध्यान में रखते हुए,

प्रतिवादियों को श्री तरलोचन सिंह की अदालत में राशि जमा करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब मामले में डिक्री विशिष्ट प्रदर्शन के लिए है और वही लागू है। इसलिए, अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की दूसरी दलील भी निराधार है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

8. इस प्रकार, यह उपरोक्त चर्चा से इस प्रकार है कि राशि जमा करने का निर्देश देने वाले डिक्री का काफी हद तक अनुपालन किया गया है। मामले की परिस्थितियों में जमा राशि को अमान्य नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, अपील के तहत आदेश किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और अपील किसी भी योग्यता से रहित है और यह विफल हो जाती है।

9. नतीजतन, मैं, निष्पादन न्यायालय के आदेश को बनाए रखते हुए, इस अपील को खारिज करता हूं, लेकिन मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरुग्राम, हरियाणा